a proposal was received from the State Government of Arunachal Pradesh. After examination, the State Government was informed that the Constitution 55th Amend ment Act, 1986, which confers special responsibility on the Governor of Arunachal Pradesh with respect to Law and Order is an enabling provision designed to authorise the Governor to intervene in special circumstances. It is not to be used in a routine manner. Nor is it intended as an encroachment on the legitimate authority of the elected Government. In view of the unique and sensitive location of the State, it was decided that the existng provisions may continue.

स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान किया जाना

2867. श्री राम देव भण्डारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी जिले (जिसे पहले दरभंगा जिले के रूप में जाना जाता था) के जिन स्वतन्त्रता सैनानियों को "ताम्रपत्र" से सम्मानित किया गया है, उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ख) मधुबनी जिले के जिन व्यक्तियों को "ताम्रपत्र" प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया है, उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ग) क्या वे पदक उन्हें दिये जायेंगे, यदि वे उन्हें अब लेने के लिये तैयार हों ; और

(घ) क्या सरकार इससंबंध में उनसे पत्र-व्यवहार करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दरभंगा और मधुबनी नामक दो वर्तमान जिलों के निम्नलिखित तीन स्वतन्त्रत सेनानियों को ताम्रपत्रों से सम्मानित किया गया है :—

क्रम संख्या	नाम और पता
1.	डा. वैद्यनाथ झा जिला मधुबनी
2.	श्री दिगम्बर ठाकुर जिला मधुबनी
3.	श्री शोभा कान्ता झा जिला दरभंगा

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार किसी भी स्वतन्त्रता सेनानी ने "ताम्रपत्र" लेने से इन्कार नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

Implementation of Bodo Accord

2868. SHRI RATAN BAHADUR RAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bodo Accord is yet to be implemented due to various reasons;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to protect/save the accord in the greater interests of North East?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (c) Substantial progress has been made in implementing the Bodo Ascord. This inter-alia, includes enactment of the Bodoland Autono mous Council Act, 1993, constitution of an Interim Bodoland Executive Council and demarcation of the boundary of the BAC by the Government of Assam. Speedy implementation of the Accord continues to receive utmost attention. of the Central and the State Governments.